RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 223 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » बुधवार » 11-03-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

तमिलनाडु में गरीबों का सशक्तिकरण

1.1+ करोड़ घरों तक नल से स्वच्छ जल और 41+ लाख उज्जवला गैस कनेक्शनों से धुआं-मुक्त रसोई, बेहतर स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित

पीएम आवास योजना के तहत लगभग 14+ लाख परिवारों को पक्के घर, अपने घर का सपना हो रहा पूरा

सौभाग्य योजना के तहत 100% घरों में बिजली कनेक्शन, अब हर घर रोशन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3.6+ करोड़ लाभार्थियों को हर माह मुफ्त अनाज, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

1.8+ करोड़ जन धन खाते खुले, वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता को मजबूती

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 1.2+ करोड़ लोग जुड़े, जीवन बीमा कवरेज का विस्तार

2.5+ करोड़ लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से और 54+ लाख लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े, दुर्घटना बीमा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 4+ लाख रेहड़ी-पटरी वालों को ₹1,000+ करोड़ के ऋण, आत्मनिर्भरता और आजीविका को बढ़ावा, जीवन बीमा का सुरक्षा कवच मजबूत

विकसित भारत के लिए
विकसित तमिलनाडु
मोदी सरकार का संकल्प

"हमारा सामूहिक लक्ष्य विकसित भारत के लिए एक विकसित तमिलनाडु है। केंद्र सरकार समावेशी विकास और राज्य की प्रगति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

CBC 01101/13/0033/2526

सरकार ने गैस आवंटन में बदलाव किया: एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी को मिलेगी प्राथमिकता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन में बदलाव किया है। इसके तहत एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) को अन्य सभी क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण भारत की एक-तिहाई गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलने वाली गैस प्रमुख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। भारत अपनी 19.1 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन गैस खपत का लगभग आधा हिस्सा आयात के जरिये पूरा करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकर की आवाजाही रुकने के कारण पश्चिम एशिया से आने वाली करीब छह करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन की गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। बची हुई तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को नए सिरे से प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया गया है ताकि एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी की मांग का 100 प्रतिशत, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की 80 प्रतिशत और उर्वरक इकाइयों की 70 प्रतिशत जरूरत पूरी की जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम स्थिति पर

मिनट-दर-मिनट नजर रख रहे हैं और बदलती जरूरतों को लेकर सतर्क हैं। प्रमुख क्षेत्रों की समूची मांग पूरी करने के लिए अभी गैस आवंटन को नए सिरे से प्राथमिकता दी गई है।

यह आवंटन मुख्य रूप से एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया गया है, जो पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण रसोई गैस की लगभग आधी आपूर्ति प्रभावित होने के बाद दबाव में आ गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित हो और युद्ध की स्थिति के बावजूद अन्य उद्योगों को उनकी आपूर्ति का 70 से 80 प्रतिशत मिलता रहे।'' उन्होंने कहा, ''हम अपने घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है और घबराने का कोई कारण नहीं है।''

सोमवार देर रात जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी नवीनतम आदेश एलएनजी की बिक्री से संबंधित सभी लंबित अनुबंधों और अन्य वाणिज्यिक समझौतों को रद्द कर देगा। अधिसूचना में कहा गया है कि इससे बची हुई गैस का आवंटन पिछले छह महीनों के वास्तविक औसत उपयोग

मोदी 13 मार्च को गुवाहाटी से पीएम-किसान की 22वीं किस्त के 19,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 22वीं किस्त का डिजिटल रूप से अंतरण करेंगे। इसके माध्यम से 9.32 करोड़ किसानों को लगभग 19,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा।

फरवरी, 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक पात्र किसान को तीन

किस्तों में सालाना 6,000 रुपए प्रदान करती है। खरीफ फसलों की बुवाई के सत्र से ठीक पहले जारी होने वाली इस राशि से किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे आवश्यक कृषि आदान जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, प्रधानमंत्री 13 मार्च को गुवाहाटी से पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। आमतौर पर ये किस्तें फरवरी-मार्च, जून-जुलाई और अक्टूबर के दौरान जारी की जाती हैं। योजना के पिछले आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2025 में 19वीं किस्त के रूप में 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे। इसके बाद अगस्त, 2025 में 20वीं किस्त के तहत 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए और नवंबर, 2025 में 21वीं किस्त के रूप में नौ करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। 21वीं किस्त तक लगभग 4.09 लाख करोड़ रुपए के कुल वितरण के साथ पीएम-किसान सम्मान निधि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रमों में से एक बनी हुई है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए नीति बनाएगी गोवा सरकार: मंत्री

पणजी/भाषा। गोवा सरकार के वन मंत्री विश्वजीत राणे ने मंगलवार को कहा कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडल का अध्ययन करने के बाद मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष यूरी अलेमाओ के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही। मंत्री ने कहा कि उन्हें इस समस्या की गंभीरता का पता है क्योंकि पैंथर, बायसन, बंदर और तेंदुए जैसे जंगली जानवर मानव बस्तियों में घुस रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जंगल क्षेत्रों में सही पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं ताकि वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास में ही रहें।

चांदी में 10,975 रुपए का उछाल, सोना भी मजबूत

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमतों में 10,975 रुपए का उछाल आया और यह 2.79 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं, सोने की कीमत में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी मज़बूत वैश्विक रुझानों के चलते हुई, क्योंकि डॉलर की कमजोरी ने इस 'सुरक्षित निवेश' वाली परिसंपत्ति की मांग को बढ़ा दिया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद चांदी की कीमत में 10,975 रुपए, या 4.09 प्रतिशत का ज़बर्दस्त उछाल आया। सोमवार के बंद स्तर 2,68,300 रुपए प्रति किलोग्राम के मुकाबले मंगलवार को यह बढ़कर 2,79,275 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में 400 रुपए, या 0.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1,64,700 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया।

मुंबई हवाई अड्डे पर 22 किलो नशीली दवा 'एटोमिडेट' जब्त

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने मुंबई हवाई अड्डे पर एलोवेरा पाउडर के रूप में छिपाकर मलेशिया भेजी जा रही 22 किलोग्राम दवा 'एटोमिडेट' जब्त की है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस दवा को हवाई माल ढुलाई के जरिए अवैध रूप से निर्यात किया जा रहा था। यह जब्ती एटीएस द्वारा इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद की गई है। रविवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सूरत निवासी निकुंज गाधिया, चेतन वावडिया और भौतिक पदमनी के रूप में हुई है। एटीएस के अनुसार, सूचना मिली थी कि कुछ लोग दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में इस दर्द निवारक दवा का निर्यात कर रहे हैं, जहां स्थानीय कानूनों के तहत इसे मादक या मन:प्रभावी पदार्थ के रूप में माना जाता है। एटीएस के अनुसार, विदेशी बाजारों में यह दवा लगभग 4,000 से 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम में बेची जा रही थी।

मोदी सरकार की आलोचना करने पर झूठे मुकदमे और जेल : सिसोदिया

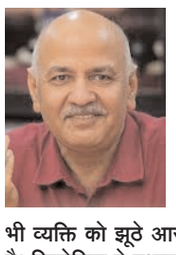

जम्मू/भाषा। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को 'तानाशाही के खिलाफ लड़ाई' जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। सिसोदिया ने प्रधानमंत्री से यह स्पष्टीकरण देने की मांग की कि अमेरिका दुनिया के सामने भारत को कैसे 'अपनी कॉलोनी' के रूप में पेश कर रहा है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह जम्मू में अपने मित्र और आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक के परिवार से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जब भी कोई आवाज उठाई जाती है, उस व्यक्ति को सीधे जेल में डाल दिया जाता है।''

हर अग्निवीर के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री धामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देहरादून/भाषा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और उनके लिए वर्दीधारी पदों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अग्निवीरों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया।

ओपी कंडारी नाम के कैडेट ने पूछा कि सरकार अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने के बाद उनके रोजगार

की क्या व्यवस्था कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्दीधारी (राज्यस्तरीय बलों) पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है जबकि इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भी अनेक क्षेत्रों में अग्निवीरों को अवसर मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा, हर अग्निवीर के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। संवाद के दौरान अग्निवीर कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे। यह पूछे जाने पर कि एक सैनिक के बेटे होने के कारण क्या उन्होंने कभी सेना में भर्ती होने के बारे में नहीं सोचा तो धामी ने कहा कि अपने पिता के साथ रहते हुए उन्होंने सेना के अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को करीब से देखा है। उन्होंने कहा, जिस प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ हमारे सैनिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उसी भावना से वह प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड की जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। हिमांशु रौतेला ने उनसे प्रश्न किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वह अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी लोग उनका परिवार हैं और सभी गांव उनके अपने गांव हैं।

गोवा के समुद्र तटों पर विदेशियों को परेशान करने वाले पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई तेज : मंत्री

पणजी/भाषा। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने कहा कि राज्य के समुद्र तटों पर सेल्फी के लिए विदेशी पर्यटकों को परेशान करने और अनुचित व्यवहार करने वाले पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। खौंटे ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि गोवा देश और दुनिया भर के पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में ऐसे मामले देखे गए जब युवा पर्यटक समुद्र तटों पर सेल्फी के लिए विदेशी आगंतुकों के पास गए और कभी-कभी वे ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे वहां का शांत वातावरण प्रभावित होता है। पर्यटन मंत्री ने कहा, ''मैंने इस मामले पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ चर्चा की है और नियम-कानून के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें संबंधित थानों के समन्वय में टीपीयू के माध्यम से समुद्र तटों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करना शामिल है।

बिरला के मन में खोट नहीं, उन्हें 'पर्ची' दी जाती है: सावंत

नई दिल्ली/भाषा। शिवसेना (उबाठा) के सांसद अरविंद सावंत ने मंगलवार को लोकसभा में दावा किया कि अध्यक्ष ओम बिरला के मन में खोट नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा उन पर 'पर्ची' के माध्यम से दबाव बनाया जाता है।

बिरला के खिलाफ विपक्ष के संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए सावंत ने यह भी कहा कि पहले की भाजपा दूसरी थी, जिसमें लोगों को सुना जाता था। उन्होंने कहा, ''मैं व्यथित हूं...व्यक्तिगत रूप से बिरला जी के साथ अच्छे रिश्ते हैं...लेकिन आसन पर मेरी मर्जी नहीं, अधिकार चलेगा। उस अधिकार का हम सम्मान करते हैं।'' दक्षिण मुंबई से लोकसभा सदस्य ने कहा, ''हमने सुमित्रा महाजन को देखा है। 2014 की

भाजपा अलग थी। उस वक्त हम साथ थे। वह डांटती थीं, हमें भी डांटा है। उस डांट में प्यार था।'' सावंत का कहना था, ''हमे नहीं लगता कि बिरला साहब के मन में खोट है। हमने उनके चेहरे पर हंसी देखी है, खुशी देखी है, लेकिन कभी-कभी उनका चेहरा गिरा हुआ देखा है। उनके पास पर्ची आती है।'' बजट सत्र के पिछले चरण में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए तो लोकसभा अध्यक्ष को 'पर्ची' देकर कहलवाया गया कि उनके कहने पर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। सावंत ने कहा कि सत्तापक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि '2जी' के समय जब भाजपा विपक्ष में थी, तब पूरे सत्र में कार्यवाही नहीं चलने दी गई थी। उन्होंने कटाक्ष किया, ''100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।'' उनका कहना था, ''हम चाहते हैं कि आप (सत्तापक्ष) बिरला साहब को मुक्त करिये, वह न्यायपूर्ण रहें।'' सावंत ने कहा कि बिरला के प्रति व्यक्तिगत रूप से आदर है, लेकिन ऐसा काम होना चाहिए कि भविष्य में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं पड़े।

पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों को बीमा समर्थन देने पर विचार: गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों को मदद देने के लिए सरकार बीमा समर्थन की नई योजना लाने की संभावना तलाश रही है।

गोयल ने कहा कि इस संबंध में निर्यात ऋण गारंटी देने वाली इकाई ईसीजीसी और अन्य विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है। हम निर्यातकों की मदद के लिए बीमा समर्थन जैसी कुछ नई योजनाएं विकसित करने पर भी विचार कर रहे हैं... इस बारे में ईसीजीसी और अन्य विभागों से चर्चा की जा रही है। एक अंतर-मंत्रालयी समूह पश्चिम एशिया संकट से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और निर्यातकों के साथ लगातार संपर्क में है। गोयल ने कहा कि सरकार उन निर्यातकों की मदद के उपाय तलाश रही है जिनका माल भेजा जा चुका है लेकिन मौजूदा हालात के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चौबीसों घंटे हालात पर नजर रखे हुए है। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच लगातार जारी हमलों से पश्चिम एशिया में

तनाव बढ़ गया है, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। यह संकट भारतीय निर्यातकों के लिए इस लिहाज से अहम है कि भारत के लिए पश्चिम एशिया प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है। इससे पहले गोयल ने 'आहार खाद्य एवं आतिथ्य मेला' को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए। भारत फिलहाल दुनिया का सातवां सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अब तक किए गए नौ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय उत्पादों के लिए निर्यात के बड़े अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा, हम अब कनाडा के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया के छह देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ भी चर्चा शुरू हुई है।

चंडीगढ़ धोखाधड़ी मामले में 645 करोड़ रुपए के दावों का निपटान: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

नई दिल्ली/भाषा। निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मंगलवार को कहा कि चंडीगढ़ की एक शाखा में सामने आए धोखाधड़ी मामले से जुड़े दावों का निपटान 645 करोड़ रुपए में कर दिया गया है और इस मामले में कोई अन्य गड़बड़ी सामने नहीं आई है। बैंक ने पिछले महीने बताया था कि चंडीगढ़ स्थित उसकी एक शाखा में हरियाणा सरकार के कुछ खातों से जुड़े मामलों में कुछ कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। बैंक ने शेयर बाजार को दी नवीनतम सूचना में कहा कि पहले इस राशि का आकार 590 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था लेकिन बाद में मिले दावों के आधार पर 645 करोड़ रुपए की मूल राशि का भुगतान किया गया है, जो प्रारंभिक अनुमान से 55 करोड़ रुपए अधिक है। बैंक ने कहा कि ये सभी दावे उसी घटना एवं संबंधित शाखा से जुड़े हैं और यह कोई नया मामला नहीं है। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि फिलहाल कोई अन्य दावा लंबित नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा कि वह इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा और बकाया राशि की वसूली के प्रयास करेगा।

सहकारी संघवाद कहने के साथ-साथ उस पर अमल भी करना चाहिए : विपक्ष ने रास में कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने दावा किया कि सहकारी संघवाद कहने के साथ साथ उस पर अमल भी करना चाहिए।

ग्रामीण मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हो रही चर्चा में भाग ले रहे तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि बढ़-चढ़ा कर आंकड़े पेश करने के बजाय सरकार को असलियत बताना चाहिए। हक ने कहा कि यहां ग्रामीण मजदूर और गरीब लोगों की बात हो रही है और लोग बंगाल में बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं और उनके हक के लिए राज्य की मुख्यमंत्री सड़कों पर धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बंगाल को आज कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ''राज्य को उसका बकाया अब तक नहीं मिला है। अदालतों के आदेशों के बावजूद यह स्थिति है। क्या सरकार अदालत के आदेशों की अवमानना कर रही है?'' राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए हक ने कहा कि मनरेगा से राष्ट्रपिता का नाम ही हटा दिया गया। ''बापू को कौन सम्मान नहीं देता? वह सबके आदरणीय हैं। फिर भी उनके नाम से परहेज क्यों ?'' उन्होंने कहा ''आप रोजगार तो दे नहीं सकते, लेकिन नियम ऐसे बना देते हैं कि लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। आधार आधारित भुगतान की व्यवस्था का नियम ऐसा ही एक नियम है।'' हक ने दावा किया कि विभिन्न मदों में राज्य का बकाया उसे अब तक नहीं मिल पाया है जबकि राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तृणमूल सदस्य ने कहा कि किसान इसी देश का हिस्सा हैं और उन्हें भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। ''उनकी समस्याएं आज भी वहीं हैं। न आमदनी बढ़ी, न कर्ज माफ हुआ और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली।'' चर्चा में हिस्सा ले रहीं बीजू जनता दल की सुलता देव ने कहा कि ओडिशा एक आदिवासी बहुल राज्य है और वहां की समस्याएं केंद्र के सामने बार बार उठाने के बाद हल नहीं होतीं। ''फिर आप कैसे ग्रामीण विकास की बात करते हैं। आज आदिवासियों से उनके हक छीने जा रहे हैं। उनके लिए अनाज कहां है?''

राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत में किसान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव में एक किसान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए।

कांग्रेस के अनुसार, गांधी की मुलाकात किसान संजय से पहली बार 2023 में मदीना गांव में अचानक की गई यात्रा के दौरान हुई थी और उन्होंने उनके साथ खेतों में काम करते हुए किसान परिवारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के बारे में जाना था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुबह गांव पहुंचे, जहां कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

सफेद टी-शर्ट और हरी पतलून पहने गांधी ने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया और परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों से बातचीत की। परिवार ने सम्मान स्वरूप उन्हें पगड़ी बांधी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट

किया, ''विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोनीपत में किसान संजय मलिक की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए।'' पार्टी ने पोस्ट में कहा, ''जननायक राहुल गांधी पहली बार संजय जी से 2023 में मिले थे। उन्होंने उनके साथ खेतों में काम किया और किसान परिवारों के संघर्षों की कहानियां सुनीं।'' इस पोस्ट के साथ गांधी की यात्रा की तस्वीरें भी साझा की गई हैं।

पोस्ट में लिखा है, गांधी ने संजय मलिक और उनके परिवार के सुख-दुख में साथ देने का वादा किया था। आज, 'जननायक' उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बने हैं।

इस बीच, विवाह समारोह में गांधी के साथ रहे कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 'एक्स' पर लिखा, ''जिस दौर में बड़े नेताओं में धनाढ्य पूंजीपतियों की शादियों में पहुंचने की होड़ लगी होती है, उसी दौर में राहुल गांधी ने आज उस संजय किसान की बेटी की शादी में पहुंच कर अपना कन्यादान का वचन निभाया जिसके खेत में दो वर्ष पूर्व धान बुआई का कार्य किया था।''

गौरतलब है कि जुलाई 2023 में गांधी ने अचानक मदीना गांव का दौरा किया था और लोगों से बातचीत की तथा खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ समय बिताया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने धान की बुआई में हिस्सा लिया, ट्रैक्टर चलाया और खेतों में काम कर रही महिला मजदूरों द्वारा लाया गया भोजन किया था।

RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 223 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » बुधवार » 11-03-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया होता तो प्रदर्शन अच्छा होता : रीजीजू

6 वैश्विक युद्धोन्माद के बीच विश्व शांति की पुकार

7 टीवी के बाद अब ओटीटी पर जादू बिखेरेंगी रूप दुर्गापाल

फर्स्ट टेक

बांग्लादेश को भारत से मिला 5,000 टन डीजल

ढाका/भाषा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ईंधन की किल्लत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, बांग्लादेश को भारत से डीजल मिलना शुरू हो गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि शुरुआती तौर पर 5,000 टन डीजल बुधवार तक मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसी) के प्रवक्ता ने कहा, ''हमें सोमवार दोपहर से असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एनआरएल) से बांग्लादेश-भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से (उत्तर-पश्चिमी) दिनाजपुर स्थित डिपो में डीजल मिलना शुरू हो गया है।'' उन्होंने बताया कि 5,000 टन डीजल आने में लगभग 45 घंटे लग सकते हैं। यानी यह प्रक्रिया बुधवार शाम तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा, ''हम यहां प्रति घंटे पाइपलाइन के जरिये लगभग 113 टन प्राप्त कर रहे हैं।'' इससे पहले, बांग्लादेश ने कहा था कि भारत एक दीर्घकालिक समझौते के तहत और 1,80,000 टन की वार्षिक आपूर्ति व्यवस्था के हिस्से के रूप में 5,000 टन डीजल भेजेगा।

एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हवाई टिकट पर ईंधन अधिभार लगाएंगी

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में तेजी आने पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से प्रत्येक घरेलू उड़ान के टिकट पर 399 रुपये का ईंधन अधिभार लागू करेंगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी ईंधन अधिभार बढ़ाया जाएगा। मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि नई अधिभार प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में, 12 मार्च से घरेलू और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के लिए उड़ानों पर 399 रुपये प्रति टिकट का ईंधन अधिभार लागू होगा। बयान में कहा गया कि पश्चिम एशिया की उड़ानों के लिए अधिभार 10 डॉलर, अफ्रीका के लिए 90 डॉलर और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए 60 अमेरिकी डॉलर होगा।

11-03-2026	12-03-2026
सूर्यास्त 6:18 बजे	सूर्योदय 6:18 बजे

BSE	NSE
78,205.98	24,261.60
(+639.82)	(+233.55)

सोना	चांदी
16,647 रु.	274,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

दौर पर ग़ौर

रिश्वतखोरी हो गई आम,
मंहगाई की लग रही झड़ी।
रुजगार लापता शहरों से,
वादों की रपटें घड़ी-घड़ी।
असमंजस में बैठे किसान,
उम्मीदें उनको बड़ी-बड़ी।
नेता निंदा में लगे पड़े,
जनता की दिखती खाट खड़ी।।

युवा आकांक्षाएं भारत की सबसे बड़ी पूंजी : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश की ''सबसे बड़ी पूंजी'' हैं और उनके नवाचार एवं योगदान की इच्छा राष्ट्र के भविष्य के लिए एक प्रमुख ताकत है।

दिव्यांगजन कौशल योजना पर बजट के बाद एक वेबिनार में मोदी ने कहा कि इस तरह के परामर्श की नई परंपरा जन भागीदारी के शक्तिशाली उदाहरण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक विचार पेश करने को लेकर विशेषज्ञों, हितधारकों और लाभार्थियों को एक साथ लाते हैं।

मोदी ने कहा, ''आज भारत की सबसे बड़ी ताकत गांवों, कस्बों और शहरों के युवाओं की आकांक्षाओं में निहित है, जो देश के भविष्य के लिए कुछ नया करना और सार्थक योगदान देना चाहते हैं।''

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे भारत एक नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, देश को इस क्षमता का फायदा उठाने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को लगातार आधुनिक बनाना होगा।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्रीय बजट में दिव्यांगजन कौशल योजना की घोषणा का उद्देश्य दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार से जुड़े कौशल विकास को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच साझेदारी महत्वपूर्ण होगी।

वेबिनार में विशेषज्ञों ने जोर दिया कि दिव्यांगजन के लिए बाजार-आधारित कौशल ऐसे हों, जो समुदाय की आकांक्षाओं को उद्योग की मांग के साथ जोड़े और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) अध्ययन और रोजगार प्रणाली में समाहित करे। चर्चा में समावेशी नियुक्ति, सुलभ प्रशिक्षण उपकरण, उद्यमिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई-सक्षम दूरस्थ कार्य अवसरों के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली/भाषा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। एक बयान में यह जानकारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि इंडिगो पिछले तीन माह में अपने परिचालन में बड़े व्यवधान का सामना कर रही है। बयान में कहा गया है कि नए सीईओ की नियुक्ति तक एयरलाइन के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया अंतरिम व्यवस्था के तहत इंडिगो के प्रबंधन का कामकाज देखेंगे।

इंटरग्लोब एविएशन के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा, राहुल एयरलाइन के प्रबंधन का कार्य संभालने लौट रहे हैं ताकि कंपनी की संस्कृति को मजबूत किया जा सके, संचालन की उत्कृष्टता को और बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को बेहतर देखभाल, भरोसेमंद सेवा और पेशेवर अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया जा सके।

इंटरग्लोब एविएशन एयरलाइन का परिचालन इंडिगो ब्रांड नाम से करती है।

विनम्रता और संयम के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करें आयकर अधिकारी : राष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि कर अधिकारियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग विनम्रता, संयम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए।

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करने आए भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि कर अधिकारियों से ऐसे निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है जो न्यायसंगत, कुशल और व्यावसायिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ पर आधारित हों।

मुर्मू ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि आपके निर्णय और कार्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने तथा देश के राजस्व की रक्षा करने के बीच सही संतुलन स्थापित करेंगे।''

राष्ट्रपति ने कहा कि आईआरएस अधिकारी होने के नाते, उन्हें अपने आचरण और निर्णय लेने में सावधानी से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा का दायित्व कर संग्रह से कहीं अधिक व्यापक है।

राष्ट्रपति ने कहा, ''जटिल वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण करने, सीमाओं के पार अवैध वित्तीय प्रवाह का पता लगाने और जटिल कॉरपोरेट संरचनाओं को समझने की आपकी क्षमता आपको विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में राष्ट्र की यात्रा को आगे बढ़ाने में अपरिहार्य भागीदार बनाती है।''

राष्ट्रपति मुर्मू ने आईआरएस (आयकर) के 79वें बैच के प्रशिक्षुओं अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, ''आईआरएस अधिकारी के रूप में, आप यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि करों की वसूली निष्पक्षता, दक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाए।''

भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे : बालेंद्र शाह

काठमांडू/भाषा। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेंद्र शाह ने मंगलवार को नेपाल-भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत और उन्हें अधिक परिणामोन्मुखी बनाने का विश्वास व्यक्त किया। रैपर से नेता बने 35 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के पहले मधेसी और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये बातें कही और पार्टी की चुनावी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने पोस्ट में कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। शाह ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक, घनिष्ठ और बहुआयामी संबंधों को अधिक मजबूत, गहरा व परिणामोन्मुखी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। नेपाल में संसदीय चुनावों में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत मतगणना मंगलवार को पूरी होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने 165 में से 125 सीटें जीत ली हैं, जिससे वह बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। पार्टी ने आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत 49,74,957 वोट हासिल किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को आरएसपी प्रमुख रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हुए दोनों देशों की पारस्परिक समृद्धि, प्रगति और कल्याण के लिए उनके साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता जताई। शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत सरकार और भारतीय जनता को भारतीय क्रिकेट टीम के लगातार दो बार विश्व कप खिताब जीतने पर बधाई दी।

न्यायालय ने शरिया कानून के प्रावधानों को रद्द करने की याचिका पर कहा :

यूसीसी का समय आ गया है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

- हमें निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए विधायी शक्ति का सहारा लेना होगा।
- एक पुरुष की एक पत्नी' का नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा है।

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अब 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को ''एक बहुत अच्छा मामला'' बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका (सरकार) को ही विचार करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करता है, तो इससे कानून में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को नियमित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा, ''सुधारों के प्रति हमारे अति-उत्साह में, हम उन्हें वंचित कर सकते हैं, और उन्हें पहले से मिल रहे अधिकारों से कम मिल सकता है। यदि 1937 का शरिया कानून खत्म हो जाता है, तो फिर सवाल क्या उठता है? क्या इससे एक अनावश्यक शून्य उत्पन्न नहीं होगा?''

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, ''भेदभाव के मुद्दे पर आपका मामला बहुत मजबूत है, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि न्यायालय इस मामले को विधायिका के विवेक पर छोड़ दे, जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार प्राप्त है?''

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''इसका उत्तर है समान नागरिक संहिता।'' न्यायमूर्ति बागची ने इस बात पर जोर दिया कि 'एक पुरुष की एक पत्नी' का नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, ''लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अदालत सभी बहुविवाहों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है? इसलिए, हमें निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए विधायी शक्ति का सहारा लेना होगा।'' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधायिका के विवेक पर छोड़ना ही सबसे अच्छा होगा। न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा, ''इस अदालत ने बार-बार विधायिका से यह सिफारिश की है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करे।

रक्षा मंत्री ने जारी किया 'दृष्टिकोण पत्र-2047'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पत्र जारी किया, जिसमें भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक रणनीतिक सुधार, दक्षता बढ़ाने के उपाय और संगठनात्मक परिवर्तन की एक श्रृंखला की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह दृष्टिकोण पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के आठ महीने बाद जारी किया गया। पिछले साल सात से 10 मई के बीच हुए इस संघर्ष के बाद, सेना के तीनों अंगों (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) से कहा गया कि वे इस संघर्ष से मिले अनुभव का लाभ उठाने के लिए काम करें।

इस संघर्ष के बाद, तीनों सेनाओं को इससे मिले अनुभव पर काम करने के लिए कहा गया था।

'रक्षा बल दृष्टिकोण 2047: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना की रूप रेखा' में सेना को एक एकीकृत, बहु-क्षेत्रीय और सतर्क बल में बदलने की परिकल्पना की गई है, जो विरोधियों को रोकने और किसी भी संघर्ष का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम हो।

ईरान ने दबाव बनाने की रणनीति के तहत इजराइल, खाड़ी देशों पर नए हमले किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। ईरान ने मंगलवार को दबाव बनाने की नीति के तहत इजराइल और खाड़ी देशों पर नये हमले किए। इस युद्ध ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है।

संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मिसाइलों की चेतावनी वाले सायरन बजने लगे, जबकि बहरीन में अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने राजधानी में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 29-वर्षीय एक महिला मारी गई, जबकि आठ

इजराइल ईरानियों को मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए ईरानी आगे आएं : नेतन्याहू

यरूशलम/भाषा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरानियों को ''तानाशाही शासन से मुक्ति'' दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन देश में कोई भी राजनीतिक परिवर्तन अंततः वहां की जनता पर निर्भर करेगा। सोमवार को क्षेत्रीय संघर्ष के 11वें दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कमान केंद्र पहुंचे नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का अभियान ईरानी नेतृत्व को कमजोर कर रहा है।

ईरान से युद्ध जल्द समाप्त होने की संभावना, लेकिन

तेल आपूर्ति बाधित हुई तो और कठोर हमले करेंगे : ट्रंप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस्लामी गणराज्य वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करता है तो लड़ाई और तेज हो सकती है।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद उनके पुत्र अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। इसके एक दिन बाद ही तेल की कीमतें कुछ समय के लिए 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।

निवेशकों का मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के 10 दिन बाद ईरान अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है।

राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाएं कार्ययोजना : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सुदृढ़ राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार राजस्व संग्रहण को मजबूत करने के साथ-साथ पारदर्शी और सरल कर व्यवस्था विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य रही है। शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति, खनन ब्लॉक्स की नियमित नीलामी, पारदर्शी कर व्यवस्था सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं जिससे गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष समान अवधि में राज्य सरकार को 7.10 प्रतिशत की राजस्व अर्जन में वृद्धि हुई है। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी राजस्व आय में वृद्धि के लिए कार्ययोजना बना कर कार्य करें। साथ ही, सभी विभागों की राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समिति का भी गठन किया जाए जो नियमित तौर पर विभागवार प्रगति का आकलन करे। शर्मा ने कहा कि जीएसटी सुधारों से आमजन को राहत मिली है और इस क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स में प्रदेश देशभर में अग्रणी है तथा इससे करदाताओं को भी लाभ मिला है। शर्मा ने कर चोरी और पारदर्शी कर व्यवस्था के लिए सुदृढ निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही, कर संबंधी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस सिस्टम के उपयोग करने से करदाताओं को अधिक सुगमता हुई है। राज्य में जीएसटी संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से परिवहन विभाग द्वारा भी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.51 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन हुआ है। साथ ही, ग्रीन टैक्स से आय में भी वृद्धि हुई है। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, व्हीकल स्क्रैपिंग का भी व्यवस्थित निष्पादन किया जाए।

बैठक में बताया गया कि पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा डीएलसी दरों में किए गए सुधारों से इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में स्टांप ड्यूटी से अर्जित राजस्व समान अवधि में 16.34 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं खनन पट्टों की नीलामी से राजस्व अर्जन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम के उपाय किए जाएं तथा इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल करने और आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति में किए गए नीतिगत सुधारों से इस वर्ष आबकारी से राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 7.52 प्रतिशत अधिक रहा है। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

'चिरंजीवी योजना' में बदलाव से गरीब मरीज भटकने को मजबूर : अशोक गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि उनके कार्यकाल की 'चिरंजीवी योजना' में किए गए बदलाव के कारण बजट की कमी और कुप्रबंधन पैदा हो गया है, जिससे गरीब मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधाओं के प्रति गंभीरता दिखाते हुए नयी बीमा योजना में अविलंब सुधार करना चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। गहलोत ने जोधपुर में आयुष्मान आरोग्य योजना के कारण अस्पतालों में मरीजों को हो रही परेशानी संबंधी एक समाचार का उल्लेख करते हुए कहा, जोधपुर के अस्पतालों की यह स्थिति चिंताजनक है। हमारी सरकार की 'चिरंजीवी योजना' का उद्देश्य हर राजस्थानी को इलाज की निश्चिंतता देना था, लेकिन इस योजना में किए गए बदलाव के कारण बजट की कमी और कुप्रबंधन से गरीब मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री विधानसभा में जोधपुर के अस्पतालों की बिगड़ती स्थिति के बारे में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान में उनकी रुचि नहीं दिखाई देती। उनकी सरकार न तो जोधपुर के नए अस्पतालोंदिगाड़ी, प्रतापनगर, चैनपुरा और मगरा पूंजला का निर्माण पूरा होने के बावजूद उन्हें शुरू करवा पा रही है और न ही पुराने अस्पतालों का रखरखाव और संचालन ठीक से कर पा रही है। गहलोत ने राज्य सरकार से इस मामले में गंभीरता दिखाने की मांग करते हुए कहा कि नयी बीमा योजना में जल्द सुधार किए जाएं, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने पर सदन में हंगामा, कांग्रेस विधायकों का बहिर्गमन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को घरेलू व वाणिज्यिक रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ने का मुद्दा उठा और इस दौरान विपक्षी कांग्रेस ने नारेबाजी की और सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सरकार ने महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये व वाणिज्यिक गैस के दाम लगभग 110 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इससे प्रत्येक परिवार प्रभावित होगा... सरकार न जवाबदेह है और न जिम्मेदार... जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार को 'सब्सिडी' देकर जनता को राहत देनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, होटल, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि वह सिलेंडर के दाम कम करेगी या नहीं? कांग्रेस विधायकों ने कुछ देर नारेबाजी व हंगामा करने के बाद सदन से बहिर्गमन किया।

इससे पहले प्रश्नकाल में भी इस मुद्दे को लेकर जूली व खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के बीच नोकझोंक हुई।

एक तारांकित प्रश्न के दौरान जूली ने पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं ...ऐसे में सरकार सिलेंडर के बढ़े हुए दाम की सब्सिडी अपनी तरफ से देकर राजस्थान की जनता को राहत देना चाहती है या नहीं है।' खाद्य मंत्री गोदारा ने कहा, हमारी सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है कि आम लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। भारत व राजस्थान सरकार रसोई गैस की कमी नहीं होने देंगी। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच अध्यक्ष ने अगला प्रश्न लिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी।

जयपुर के आमागढ़ किले व अम्बा माता मंदिर का होगा जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण : संजय शर्मा

जयपुर। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जयपुर शहर के आमागढ़ किले में जाने वाला मार्ग वन क्षेत्र से निकलता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वन विभाग द्वारा इस मार्ग का संधारण करवाया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आमागढ़ किले तथा यहां स्थित अम्बा माता के मंदिर में जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य भी करवाया जाएगा। वन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामकेश द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक प्रतापगढ़ के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और संधारण के लिए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में प्रावधान किया गया है। इससे पहले सदस्य रामकेश के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि जयपुर शहर के आमागढ़ किले में जाने वाला मार्ग आरक्षित वन खण्ड 92, बन्द की गढ़ी आम्बागढ़ के वन क्षेत्र से निकलता है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों से निकलने वाले रास्तों की मरम्मत और निर्माण कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही करवाये जाने का प्रावधान है।

शर्मा ने कहा कि अम्बा माता जी के मन्दिर में दर्शन के लिए जाने वाली आम जनता को नहीं रोका जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभागीय स्तर पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार व किले की मरम्मत करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मिशन 'हरियालो राजस्थान' के तहत आगामी मानसून में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी मानसून-2026 में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 से 2028 तक राज्य में कुल 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी हितधारक विभाग राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें तथा नवगठित जिलों के अनुसार जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापत करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि व्यापक पौधारोपण के माध्यम से राज्य में हरित आवरण बढ़ाने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मिशन हरियालो राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम को जनभागीदारी से जोड़ते हुए विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि इस अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा सके।

उन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए तीन-स्तरीय टास्क फोर्स व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कार्य करेगी।

उन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम के लिए विस्तृत समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार 31 मार्च 2026 तक पौधारोपण स्थलों का चयन किया जाएगा। अप्रैल से जून 2026 के दौरान गड्ढे खोदने, फेंसिंग सहित अन्य तैयारियाँ की जाएंगी। 15 जून से 15 जुलाई के बीच नर्सरियों से पौधों की खरीद की जाएगी तथा 1 जुलाई से सितम्बर 2026 तक राज्यभर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। आनंद ने जानकारी दी कि वन विभाग की नर्सरियों में वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 626.10 लाख पौधों की तैयारी की जा रही है, जबकि वन भूमि पर पौधारोपण के लिए अतिरिक्त 200 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग पौधारोपण गतिविधियों की जानकारी नियमित रूप से हरियालो ऐप पर अपलोड करें, ताकि कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

आनंद कुमार ने अवगत कराया कि वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत 7 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य के विरुद्ध 7.22 करोड़ पौधे लगाए गए। इसी प्रकार मानसून-2025 में 10 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 11.74 करोड़ से अधिक पौधारोपण कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गई।वहीं वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों को कुल 10 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य आवंटित किया गया है।

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) पी.के. उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) सुशिखा मेहरा, मुख्य वन संरक्षक (आयोजना) एस.आर.वी. मूर्थी, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कपिल चंद्रवाल, आईजी होम दीपक कुमार सहित जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, खेल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, उद्यानिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं आवासन तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में सड़क निर्माण के प्रगतिरत कार्य जून माह तक पूर्ण होंगे : दिया कुमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ - लक्ष्मणगढ़ में दो वर्षों में 96 करोड़ रुपए की लागत से कुल 115 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 64 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं व 50 कार्य प्रक्रियाधीन है तथा शेष एक कार्य का निरस्तीकरण प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 19 जून 2026 तक सड़कों के सभी 50 प्रक्रियाधीन कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सदस्य मांगेलाल मीना द्वारा इस संबंध में पूरक प्रश्न का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 में विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ - लक्ष्मणगढ़ में 10 करोड़ रुपए के सड़क कार्यों की घोषणा की गई है।

इससे पहले सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए मूल प्रश्नों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों के नवीनीकरण के मापदण्ड राज्य सड़क नीति 2013 के अनुसार निर्धारित हैं। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में 67 क्षतिग्रस्त एवं नॉन पेचेबल सड़कें थी। जिनमें से 26 सड़कों के कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं एवं कार्य प्रगतिरत है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में वर्तमान में प्रदेश की सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। घोषणानुसार कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का चयन कर नवीनीकरण करवाया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और उनकी माता के बीच गृह-कलह की तस्वीरें वायरल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल मंगलवार सुबह जब पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के साथ अपने पैतृक निवास पहुंचे, तो वहां हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।

अपनी ही माता और बेटे के साथ उनकी तीखी बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर मारवाड़ की जनता में आक्रोश और दुख दोनों देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों में दावा किया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह पुलिस बल लेकर अपने घर पहुंचे, लेकिन सूत्रों और पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है: पुलिस विभाग के अनुसार, इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक मुकदमा या परिवाद दर्ज नहीं हुआ है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, वीडियो में जो वर्दीधारी दिख रहे हैं, वे आधिकारिक पुलिसकर्मी नहीं बल्कि प्राइवेट सिक्योरिटी के जवान हो सकते हैं, जो संभवतः पूर्व में उनकी सुरक्षा में तैनात रहे हैं। वीडियो में स्व. जसवंत सिंह की 90 वर्षीय पत्नी अपनी दहलीज की रक्षा के लिए अपने पुत्र के सामने खड़ी नजर आ रही हैं। इसे पारिवारिक संपत्ति या मर्यादा से जुड़ा विवाद माना जा रहा है। इस घटना ने मारवाड़ के संस्कारों और 'मां' के सम्मान को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

वायरल हो रहे संदेशों में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं: 90 साल की बुजुर्ग मां आज अपनी तपोभूमि और उस दहलीज की रक्षा के लिए अपने ही पुत्र के सामने चट्टान बनकर खड़ी है। क्या शस्त्रधारी गार्ड मारवाड़ की इस जननी को डरा पाएंगे?

मानवेंद्र सिंह जसोल ने हाल ही में 'सरहद की समृद्धि यात्रा' शुरू की थी, जिस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। आलोचकों का कहना है कि जो अपनी पारिवारिक दहलीज पर संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे, वे सरहद की समृद्धि का ब्लू-प्रिंट कैसे देंगे। यह पूरी तस्वीर आज समूचे मारवाड़ को स्तब्ध कर रही है।

वन, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का किया निरीक्षण

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) आमजन की समस्याओं का अंतिम पड़ाव साबित हो रही है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उनके विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली तथा परिवादियों से सीधे संवाद कर मौके पर ही संबंधित अधिकारीयों को प्रकरणों के निस्तारण कर कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के परिवादियों से संवाद के दौरान बूंदी जिले के लाखेरी के पंकज सुमन द्वारा बताया गया कि मेन रोड पर लगे पीपल के पेड़ मे से गुजर रही बिजली लाइन आमजन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मौके पर ही बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा को फोन कर मंगलावार शाम से पहले परिवादी की समस्या के समाधान कर की गई कारवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीकर के महेश कुमार खुडानिया ने समस्या के समयबद्ध समाधान हो जाने पर राज्य सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जयपुर के विष्णु द्वारा दर्ज केमिकल फेक्ट्री से प्रदूषण की शिकायत पर आनंद कुमार ने संबंधित अधिकारी को औचक निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल समस्याओं का अंतिम पड़ाव होना चाहिए। इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का किया अनुमोदन, मंडियों और यार्डों का तेजी से होगा विकास : भजनलाल

जयपुर/दक्षिण भारत। प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने दिशा में राज्य सरकार निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मण्डी विकास से संबंधित भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति से मण्डी समितियों के प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। नीति के अंतर्गत मण्डी विकास की परियोजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति के जिन मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इसी प्रकार, भूमि अवाप्ति के ऐसे मामलें जिनमें अवार्ड जारी नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही, आपसी समझौते से भूमि के अर्जन पर भू-धारकों द्वारा मण्डी समिति को निःशुल्क नवीन भूमि समर्पित करने पर कुल समर्पित भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इस नीति से भूमि अर्जन कर उपयुक्त स्थानों पर नवीन यार्डों का निर्माण तेजी से संभव हो सकेगा। साथ ही, भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण भी हो सकेगा। कृषि उपज मण्डी समितियों में 22 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों की दी स्वीकृति मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रूपये से अधिक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री मोदी आज तिरुचिरापल्ली में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 मार्च को तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह तमिलनाडु की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की एक रैली को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा से पहले 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''राज्य भर में राजग की बढ़ती लोकप्रियता से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) परेशान है। तमिलनाडु के लोगों ने द्रमुक के कुशासन और अधूरे वादों को देखा है। यही कारण है कि वे राजग के आशा और प्रगति के एजेंडे से जुड़ रहे हैं।''

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ''इससे विशेष रूप से दक्षिणी तमिलनाडु में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। शाश्वत संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध मदुरै शहर अब वैश्विक स्तर पर अपने संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है।'' शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचा, ग्रामीण कनेक्टिविटी, राजमार्ग विकास और रेलवे सेवाएं शामिल हैं। वह दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे तमिलनाडु की रेल कनेक्टिविटी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत समेत अन्य क्षेत्रों से और मजबूत होगी, जिससे यात्रियों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

केरल, तमिलनाडु के दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एलडीएफ, यूडीएफ और द्रमुक पर हमला बोला

चेन्नई/नई दिल्ली। केरल और तमिलनाडु के दौरे से पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के ''लूट और कुशासन'' के विपरीत राजग का सुशासन एजेंडा मजबूती से खड़ा है, जबकि द्रमुक तमिलनाडु में राजग की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह केरल और तमिलनाडु के दौरे को लेकर उत्सुक हैं, जहां वह बुधवार को एर्नाकुलम और तिरुचिरापल्ली में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केरल पहुंचने पर मोदी 'अखिल केरल धीवरा सभा' के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''मछुआरों के कल्याण के लिए इस संस्था द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। एक अन्य कार्यक्रम में, विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा या उनकी आधारशिला रखी जाएगी। ये कार्य ऊर्जा, राजमार्ग, ग्रामीण अवसंरचना, रेलवे आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं।'' इसके बाद, दोपहर लगभग 2:15 बजे मोदी केरल के एर्नाकुलम में आयोजित होने वाली राजग की रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ''एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के कुशासन और लूट के विपरीत राजग का सुशासन एजेंडा मजबूती से खड़ा है। राजग विकासोन्मुखी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेगा और केरलम के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।''

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सड़क, रेलवे और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। मोदी ने कहा, ''कल, 11 मार्च को शाम लगभग 6:30 बजे, मैं तिरुचिरापल्ली की रैली में तमिलनाडु के राजग नेताओं के साथ शामिल होऊंगा। द्रमुक राज्य भर में राजग की बढ़ती लोकप्रियता से स्पष्ट रूप से घबराई हुई है। तमिलनाडु के लोग द्रमुक के कुशासन और अधूरे वादों को देख चुके हैं। इसीलिए वे राजग के आशा और प्रगति के एजेंडे से जुड़ रहे हैं।'' एक दिवसीय दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री दक्षिणी राज्यों में 16,450 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे।

वसंतबेन चन्दूभाई शाह हाईस्कूल का हुआ वार्षिकोत्सव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां टी. नगर में मौजूद गुजराती माम्बलम समाज के प्रशासकों द्वारा वसंतबेन चंदूभाई शाह मैट्रिकुलेशन स्कूल ने हाल ही में स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया।

प्रार्थना के बाद, मंच पर मौजूद लोगों ने दीपक जलाया उसके बाद, स्कूल के सचिव अरविंदभाई मेहता ने स्वागत भाषण में यहां के जाने-माने श्रीमिठाई के किरण कुमार पटेल और उनकी पत्नी हिनाबेन पटेल कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर मौजूद थे।

समाज के उपाध्यक्ष मितेशभाई पटेल और सचिव अरविंदभाई मेहता ने अतिथि का स्वागत किया। किरण कुमार पटेल ने अपने भाषण में स्कूल के वार्षिकोत्सव के मौके पर शुभकामनाएं दीं और फिर स्कूल के कई स्टूडेंट्स को प्रमाणपत्र और पुरस्कार दिए। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा ई सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से पेश किए। वार्षिकोत्सव के मौके पर स्कूल के अध्यक्ष चंद्रकांत भाई एम. टोलिया ने बधाई संदेश दिया। वार्षिकोत्सव के मौके पर स्कूल के पदाधिकारी अरविंदभाई मेहता, मितेशभाई पटेल, सुरेशभाई पटेल, हर्षदभाई मेहता, कल्पेशभाई पटेल, हसमुखभाई शेलत, प्रकाशभाई शेलत, प्रधानाचार्य डॉ. सी.एल. पाठक, स्कूल के शिक्षक, अभिभावक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रबंधन मिस ऐश्वर्या ने किया था।

मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मदुरै/नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय मदुरै के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए ने कहा कि मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के नीतिगत निर्णय से दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इस मंदिरों के शहर को हवाई संपर्क प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसके आसपास स्थित विशाल औद्योगिक संकुल को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शहर को एक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में भी मजबूत करेगा। वैष्णव ने कहा कि कई एयरलाइन कंपनियों ने हवाई अड्डे से अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरु करने में रुचि दिखाई है। मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों और कंपनियों को आकर्षित करने की हवाई अड्डे की क्षमता शहर के ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप है। मंत्री के अनुसार, इससे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों... मीनाक्षी अम्मन मंदिर, थिरुप्पारनकुंद्रम मुरुगन मंदिर, पलामुधिरचोलाई मुरुगन मंदिर और रामेश्वरम... के लिए भी संपर्क सुविधा बेहतर होगी।

अभिनेता विजय ने टीवीके उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना शुरू किया

चेन्नई। अभिनेता से नेता बने विजय ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी टीवीके पार्टी के उम्मीदवारों का मंगलवार को साक्षात्कार लेना शुरू किया। पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है।

तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के एक सूत्र के अनुसार, पार्टी राज्य की सभी 234 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को टिकट देगी। विजय मंगलवार को पनयूर स्थित टीवीके मुख्यालय पहुंचे, जहां वह लगभग 60 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेंगे। टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वाले 4,200 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। टीवीके पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे सकती है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ नेता बुस्सी आनंद, आधव अर्जुन और अरुण राज को टी नगर, विल्लीवाक्कम और तिरुचेंगोडे निर्वाचन क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतारे जाने की संभावना है। दो फरवरी 2024 को गठित हुई नई पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। पार्टी सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को आक्रामक रूप से स्थापित कर रही है। हालांकि, टीवीके ने उसके साथ चुनावी गठबंधन करने वाले दलों को सत्ता में हिस्सेदारी की पेशकश की थी, लेकिन अभी तक कोई भी राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं हुआ है।

सीबीआई ने करूर भगदड़ मामले में टीवीके प्रमुख विजय को पूछताछ के लिए दोबारा तलब किया

चेन्नई/नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय को करूर भगदड़ मामले में 15 मार्च को दोबारा तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने जनवरी में विजय से दो बार पूछताछ की थी और नौ मार्च को अभिनेता को फिर से तलब किया था, लेकिन उन्होंने इसे 15 दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया था।

अधिकारियों ने बताया कि अभिनेता विजय ने आगामी विधानसभा चुनावों के कारण राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए यह भी आग्रह किया था कि पूछताछ चेन्नई या तमिलनाडु के किसी कार्यालय में की जाए। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने अब विजय को 15 मार्च को दिल्ली स्थित एजेंसी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने करूर से द्रमुक विधायक सेंथिल बालाजी को भी 17 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। राज्य के पूर्व मंत्री बालाजी ने एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह 17 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होकर करूर भगदड़ त्रासदी के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने एसआईटी से मामला अपने हाथ में ले लिया था, और वह 27 सितंबर, 2025 को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित मामले में सबूत जुटा रही है। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए।

अभिनेत्री पर हमला मामला :सरकार की अपील पर केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप, अन्य को नोटिस भेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोच्चि/भाषा। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता दिलीप और नौ अन्य लोगों से राज्य सरकार द्वारा दायर उस अपील पर जवाब मांगा, जिसमें 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।

उच्च न्यायालय ने अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की, जिसमें राज्य ने दिलीप और तीन अन्य लोगों को मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी है और अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा पाए छह लोगों की सजा को बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। मामले से जुड़े एक सरकारी वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की पीठ ने मामले में दोषी ठहराए गए छह व्यक्तियों और निचली अदालत द्वारा बरी किए गए चार व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। अपील में दावा किया गया है कि ''दिलीप और अन्य लोगों को बरी किए जाना पूरी तरह से अवैध और अनुचित था और इससे समाज को गलत संदेश जाता है।''

बिरला बेहतर इंसान, कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए लाया गया संकल्प : द्रमुक सांसद

चेन्नई/नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को द्रमुक के सदस्यों ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बेहतर इंसान हैं और सभी को समान अवसर देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ संकल्प इसलिए लाया गया है ताकि पद पर आसीन व्यक्ति को कर्तव्यों की याद दिलाई जा सके। सदन में द्रमुक के नेता टी आर बालू ने भी कहा कि जिस तरह लोकसभा के इतिहास में पहले भी तीन बार अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उन्हें हटाया नहीं जा सका, उसी तरह आज भी बिरला को पद से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि लोककभा अध्यक्ष को कर्तव्यों की याद दिलाएं। उन्होंने कहा, ''बिरला बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।'' बालू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद अगस्त, 2019 में बिरला ने खुद एक साक्षात्कार में कहा था कि ''सदन बहुमत से नहीं आम सहमति से चलता है।'' द्रमुक सांसद ने कहा, ''मेरी उम्मीद है कि उन्हें ये शब्द याद होंगे और भविष्य में इनका पालन करेंगे।''

श्री चंद्रप्रभु जैन कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट उत्सव 'कलाकृति 2026'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां के श्री चंद्रप्रभु जैन कॉलेज में कलाकृति 2026-इंटर-कॉलेजिएट कल्चरल फेस्ट मनाया गया। मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध चंद्रप्रभु जैन कॉलेज, मिंजुर ने 10 मार्चको को भगवान महावीर सभागार में अपनी सांस्कृतिक समिति के माध्यम से एक अंतर-कॉलेजिएट सांस्कृतिक उत्सव कलाकृति 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई, जिसके बाद प्राचार्य डॉ. एन. सुजाता ने स्वागत भाषण दिया, जिन्होंने छात्रों के बीच रचनात्मकता, आत्मविश्वास और समग्र विकास को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। कॉलेज के ट्रस्टी सदस्य हितेंद्र बी. मुनोथ की गरिमामयी उपस्थिति रही। परिचयात्मक नोट सचिव ललित कुमार ओ. जैन द्वारा दिया गया, जिन्होंने शैक्षणिक और सांस्कृतिक दोनों प्लेटफार्मों के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट मुख्य अतिथि कोरियोग्राफर और अभिनेत्री शांति अरविंद, अभिनेता और नर्तकी लोकेश भास्करन, अभिनेत्री रेशमा प्रसाद, गणगायिका गण उलगम धरणी थे। उन्होंने छात्रों के लिए इस तरह के जीवंत सांस्कृतिक मंच के आयोजन में संस्थान के प्रयासों की सराहना की और उन्हें समर्पण और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने राज्य सरकार एमओयू पर हस्ताक्षर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई में हाल ही में तमिलनाडु सरकार के डायरेक्टर ऑफ़ ट्रेजरीज़ एंड अकाउंट्स आईएएस एन वेंकटेश और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई जोनल हेड के शशिधर के बीच बैंक की सेंट प्रेस्टीज स्कीम के तहत तमिलनाडु राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके चलते सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अब तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ एम्पैनल्ड हो गया है ताकि बैंक की सेंट प्रेस्टीज सैलरी स्कीम के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट को रूट किया जा सके। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी अनेक लाभ उठा सकेंगे।

प्रतिभाशाली महिलाओं को अरसी अवॉर्ड्स से सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। महिला दिवस के अवसर पर सिवासंकरी टॉक्स द्वारा अरसी अवार्ड्स का आयोजन किया गया जिसमें नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया गया। इस समारोह का आयोजन टीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सह-संस्थापक फेलिक्स माइकल और अन्ना स्टेफी फेलिक्स ने किया। आयोजन कि प्रमुख सहयोगी सुस्सी हर्बल्स की कायलविझी रही। कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष सेंथिल थोंडैमान, लाइका प्रोडक्शन्स के प्रमुख तमिझ कुमारन, अभिनेता संतोष प्रताप और सतीश, शेल्वी जोथिदार एवं अंबझगन जैसे विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर अनेक क्षेत्रों की प्रतिभाशाली महिलाओं को अरसी अवार्ड्स प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कराबीनि का सुविधा समागम कार्यक्रम आज

चेन्नई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कराबीनि) के हितधारकों, बीमित व्यक्तियों, नियोक्ताओं और लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए सुविधा समागम बैठक आयोजित कर रहा है। सुविधा समागम का आयोजन 11 मार्च को अपराह्न 2.30 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, 143, स्टर्लिंग रोड, नुंगम्बाक्कम में किया जाएगा। हितधारकों (नियोक्ताओं, कर्मचारियों और लाभार्थियों) से अनुरोध है कि, वे अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। उक्त बैठक में हितधारकों के सुझावों और शिकायतों पर चर्चा की जाएगी।

केरल के मंत्री गणेश कुमार ने माफी मांगी, शिकायत को आगे नहीं बढ़ाएंगी पत्नी

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के परिवहन मंत्री के. बी. गणेश कुमार की पत्नी बिंदु मेनन ने मंगलवार को कहा कि वह अपने पति के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को आगे नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि मंत्री ने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांग ली है। बिंदु मेनन ने एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में कहा कि जब उन्होंने मंत्री के फोन नहीं उठाए तो उन्होंने मेनन की बहन को फोन कर भावनात्मक रूप से बात की। मंत्री की पत्नी ने कहा ''वह बहुत भावुक हो कर बोले कि उनकी ओर से गलती हुई है। विवाह होने के इतने वर्षों के दौरान बहुत सी गलतियां हुईं लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें छोड़ रही हूं या मीडिया में जाऊंगी या मैं कानूनी कदम उठाऊंगी।''

उन्होंने कहा, ''मेरा कभी भी उनकी या सरकार की छवि खराब करने का इरादा नहीं था। मैंने भावनात्मक आवेश में यह बात कही थी। मैं शिकायत को आगे नहीं बढ़ा रही हूं, क्योंकि उन्होंने फोन कर कहा कि हम इस मुद्दे को आपस में सुलझा सकते हैं। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। निश्चित रूप से मैं शिकायत पर आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगी। हम इसे खुद ही सुलझा लेंगे।''

बिंदु मेनन ने कहा कि मंत्री के साथ विवाह के बाद बीते 13 साल में कई मुद्दे उठे लेकिन यह ऐसा कारण नहीं है जिसके चलते वह अपना संबंध विच्छेद कर लें। उन्होंने कहा कि मंत्री ने बेवफाई के उनके दावे को खारिज कर दिया जिसके बाद उन्होंने (बिंदु ने) आपात प्रतिक्रिया सहयोग व्यवस्था यानी 112 पर फोन किया। लेकिन मंत्री ने पत्नी के इस कदम को ''पागलपन'' बताया। बिंदु ने कहा कि इसके बाद वह भावनात्मक रूप से उद्वेलित हो गईं। बिंदु मेनन ने कहा ''जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं और चूंकि वह मंत्री हैं तो यह बात सब जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है। मंत्री को जनता से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उनके साथ रहती हूं तो उन्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा ''मेरा इरादा बदला लेने का और शिकायत पर आगे जाने का नहीं है क्योंकि मेरे लिए यह कहना आसान है कि मैं कुछ नहीं चाहती और मैं इस मामले में आगे जा रही हूं। मैं यह बहुत पहले कर सकती थी लेकिन नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं।'' इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से मंत्री के इनकार करने के बाद मेनन ने सोमवार को उन पर व्याभिचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 2014 में गणेश कुमार के साथ शादी के बाद से ही वैवाहिक समस्याएं रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गणेश कुमार के कई महिलाओं के साथ संबंध होने के कारण वह पिछले कई महीनों से अलग रह रही थीं। केरल कांग्रेस (बी) के नेता गणेश कुमार ने अपनी पहली पत्नी यामिनी थंकाची से कानूनी रूप से अलग होने के बाद 2014 में बिंदु मेनन से विवाह किया था।

भाजपा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की भगवा संबंधी टिप्पणी का मजाक उड़ाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की उस टिप्पणी का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा राज्य का 'भगवाकरण' करना चाहती है।

भाजपा ने कहा कि इसकी योजना दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने वर्ष 1999 में ही बना ली थी। तिरुचिरापल्ली में नौ मार्च को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के 12वें सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष स्टालिन ने कहा, वे (भाजपा) किसी भी तरह तमिलनाडु को एक भगवा राज्य बनाने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब तक द्रमुक यहां है, चाहे कोई भी आ जाए ऐसा नहीं होगा। इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए भाजपा की तमिलनाडु इकाई के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने 'एक्स' पर एक पोस्ट किया।

उन्होंने कहा, वह आपके पिता ही थे जिन्होंने 1999 में तमिलनाडु को भगवा राज्य बनाने की योजना बनाई थी। भाजपा नेता 1999 में अटल

बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में द्रमुक के शामिल होने का संकेत कर थे। चुनाव में राजग की जीत के बाद द्रमुक नेताओं को वाजपेयी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्टालिन ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी ने अपने स्वार्थ और मुख्यमंत्री बनने की खातिर भाजपा की 'गुलामी' स्वीकार कर ली और दिल्ली में पार्टी को गिरवी रख दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पलानीस्वामी का इस्तेमाल कर भाजपा 'पूरी अन्नाद्रमुक को नष्ट' करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'भगवा भीड़' तमिलनाडु को 'निगल' जाना चाहती है कि किंतु द्रमुक ऐसा नहीं होने देगी।

सुविचार

प्रेम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है। इसे शब्दों से ज्यादा अपने व्यवहार और समर्पण से व्यक्त किया जाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कैसी हो भारत की शिक्षा व्यवस्था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने का आह्वान कर करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन को सही दिशा देने की कोशिश की है। अगर यह काम पांच दशक पहले हो जाता तो आज देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती। अब लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ चुके हैं- 'हमने स्कूल में रट-रटकर जो पाठ याद किए, मुर्गा बने, डंडे खाए, परीक्षाओं में रातभर जागकर पढ़ाई की, उसका कितना हिस्सा अब जीवन में काम आ रहा है?' क्या उस पढ़ाई को थोड़ा बेहतर बनाते हुए कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता था, जिससे वह जीवन में काम आती और लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाती? आज का विद्यार्थी उस समय ठगा हुआ महसूस करता है, जब उसे पता चलता है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के लिए कोचिंग करनी होगी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम ऐसा है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा उस नौकरी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के जीवन में कोई काम नहीं आता। देश में जैसी शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है, उसने युवाओं को कोई कौशल नहीं सिखाया, बल्कि बेरोजगारों की भीड़ पैदा की। आज स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों युवाओं को पता ही नहीं कि उनमें क्या खूबी है और वे जीवन में क्या करना चाहते हैं! कुछ युवा यह आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की, जिससे विद्यार्थी दु:खी एवं त्रस्त रहे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह बहस का विषय हो सकता है।

भारत में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल नहीं है। भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो विद्यार्थी को अच्छा इन्सान बनाए। उसे समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाए। उसे सभी देशवासियों के साथ मिलकर रहना सिखाए। वह उसकी जिज्ञासा का दमन न करे, बल्कि सोचना और सवाल करना सिखाए। साथ ही, उसकी रुचि को पहचानकर कम-से-कम कोई एक कौशल जरूर सिखाए, जिससे उसे भविष्य में रोजगार मिले। वर्तमान में लाखों युवा ऐसे हैं, जो बेरोजगारी के कारण परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ताने सुन रहे हैं। उनकी पीड़ा कौन समझेगा? नेता तो चुनावी मौसम में सरकारी नौकरियां देने की घोषणा कर देते हैं। सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी? जिन्हें मिलती भी हैं, उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है? क्या इस तरह बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? बेरोजगारी का एक ही समाधान है- युवाओं को कौशल सिखाएं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। इसकी शुरुआत स्कूल से ही हो। पाठ्यक्रम से उस सामग्री को कम करें या हटाएं, जिसकी जीवन में कम उपयोगिता है या कोई उपयोगिता नहीं है। उसके बारे में सामान्य जानकारी देना काफी रहेगा। रटने और ज्यादा नंबर लाने पर नहीं, बल्कि संभावनाओं और समाधान पर जोर दें। स्कूली पाठ्यक्रम की भाषा शैली में बहुत सुधार की जरूरत है। कुछ सुधार हुआ भी है, लेकिन काफी गुंजाइश है। उसमें रोचकता का समावेश होना चाहिए। किताब ऐसी न हो, जिसकी चार पंक्तियां पढ़ते ही कोई विद्यार्थी सोचे- 'यह तो मेरे लिए नहीं लिखी गई है!' हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वहां रोजगार की संभावनाएं ढूंढ़ने पर खास जोर दिया जाए। राजस्थान में ऐसे लाखों व्यक्ति हैं, जिन्होंने स्कूल में भूगोल की किताब में समुद्र की गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उन्हें अपने गांव के मौसम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। वे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी आदि के उद्योगों के बारे में जानते हैं। उन्हें अपने गांव में उद्योगों से जुड़ीं संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार समय की मांग है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तुरंत लागू करना चाहिए।

ट्वीटर टॉक

नई दिल्ली में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2026 कार्यक्रम में नारी शक्ति का अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजसेवा, शिक्षा, कला और उद्यमिता आदि क्षेत्रों में योगदान देकर ये बहनें आज स्वयं की एक मजबूत पहचान रखती हैं।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

जनसेवा के प्रति आपका समर्पण, लोगों के प्रति आपका स्नेह और समाज के कल्याण के लिए किया गया आपका निरंतर कार्य सदैव प्रेरणादायी रहेगा। आपकी सरलता, आपका व्यक्तित्व और जनहित के लिए आपका योगदान हमारी स्मृतियों और परंपराओं में सदैव जीवित रहेगा।

-वसुंधरा राजे

आज भारत सरकार में भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी जी के दिल्ली स्थित निवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान विभिन्न समसामयिक राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विस्तृत और सार्थक संवाद हुआ।

-अर्जुनराम मेघवाल

प्रेरक प्रसंग

सफलता का रहस्य

अमेरिका के विश्व विख्यात उद्योगपति मिस्टर कारनेगी के पास एक जापानी इंजीनियर आया। वह कारनेगी के कारखाने का अवलोकन करने के बाद बहुत प्रभावित हुआ। भोजन के समय उसने मिस्टर कारनेगी से पूछा, 'आपने इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। इस सफलता का रहस्य क्या है?' उद्योगपति ने कहा, 'सही समय पर सही निर्णय लेना।' उसने दूसरा प्रश्न किया, 'सर, आप सही निर्णय कैसे ले पाते हैं?' उसे उत्तर मिला, 'अनुभवों के आधार पर।' अब इंजीनियर ने तीसरा प्रश्न किया, 'आपने अनुभव प्राप्त कैसे किए?' मिस्टर कारनेगी ने इंजीनियर के कंधे पर हाथ रखा तथा बोले, 'बेटा गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से अनुभव होते हैं। उन गलतियों को दोहराएं नहीं। यही संकल्प अनुभव को आगे बढ़ाता है तथा अनुभव व कठोर परिश्रम ही सफलता के शिखर पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है।' जापानी इंजीनियर चंद शब्दों में संसार के शीर्षस्थ उद्योगपति की सफलता का रहस्य समझ गया था।

सामयिक

वैश्विक युद्धोन्माद के बीच विश्व शांति की पुकार

ललित गर्ग
मोबाइल : 9811051133

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी जिसमें शक्ति को नियमों और संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके। लगभग आठ दशकों तक यह वैश्विक व्यवस्था अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद किसी-न-किसी रूप में कायम रही। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, बहुपक्षीय समझौते, कूटनीतिक संवाद और साझा नियम-इन सबका उद्देश्य यही था कि दुनिया 'मत्स्य-न्याय' यानी शक्तिशाली द्वारा कमजोर को निगल जाने की प्रवृत्ति से बची रहे। इसी सोच के तहत युनाइटेट नेशनस, वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनाइजेशन, यूनेस्को और अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने विश्व राजनीति को पूरी तरह आदर्श नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कम-से-कम इतना अवश्य सुनिश्चित किया कि शक्ति के साथ नियम और नैतिकता का एक आवरण बना रहे। परंतु आज यह व्यवस्था अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है।

विश्व राजनीति में एक नया रुझान तेजी से उभर रहा है जिसमें सहयोग, संवाद और बहुपक्षीयता की जगह एकपक्षीय कार्रवाई, सैन्य शक्ति और त्वरित लाभ की मानसिकता को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका की नीतियों ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। जो देश कभी वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था का प्रमुख निर्माता और संरक्षक था, वही अब अनेक अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संस्थाओं से दूरी बनाता दिखाई देता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही यह संकेत मिल गया था जब अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेंट अग्रीमेंटस, इरान न्यूक्लियर डील्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को जैसी संस्थाओं से खुद को अलग करने की प्रक्रिया शुरू की। इन कदमों का संदेश यह था कि यदि किसी समझौते से तात्कालिक राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। इससे वैश्विक सहयोग की उस भावना को गहरा आघात पहुंचा, जो दशकों से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला रही है।

आज स्थिति और भी जटिल हो गई है। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष सामान्य घटनाओं की तरह स्वीकार किए जाने लगे हैं। चार वर्षों से जारी रुस-यूक्रेन युद्ध और दो वर्षों से चल रहा गाजा युद्ध इसका सबसे दुखद एवं विडम्बनापूर्ण उदाहरण हैं। इन संघर्षों ने लाखों लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है, शहरों को खंडहर में बदल दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह किसी स्थायी समाधान की ओर नहीं ले जाता। युद्ध में विजय का दावा करने वाले भी अंततः विनाश और पीड़ा के साथ ही जीते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध ने कभी भी मानवता को गौरव नहीं दिया; उसने

केवल तबाही, भय और अस्थिरता को जन्म दिया है। युद्ध के परिणामस्वरूप पर्यावरण का भारी नुकसान होता है, आर्थिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, रोजगार के अवसर घटते हैं और समाज में असुरक्षा तथा अविश्वास की भावना गहरी हो जाती है।

आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि युद्ध और हिंसा धीरे-धीरे सामान्यीकृत होते जा रहे हैं। अनेक बार युद्ध का उद्देश्य वास्तविक समाधान नहीं बल्कि घरेलू राजनीति में छवि निर्माण, शक्ति प्रदर्शन या आंतरिक संकटों से ध्यान हटाना बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वैश्विक नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों कमजोर पड़ते हैं। यदि शक्तिशाली देश ही नियमों को तोड़ने लगें तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। मानवाधिकारों के प्रश्न पर भी दोहरे मानदंड दिखाई देते हैं। किसी एक देश की आलोचना की जाती है, लेकिन उसी तरह के कृत्यों पर दूसरे देशों के संदर्भ में चुप्पी साध ली जाती है। इससे मानवाधिकार एक सार्वभौमिक मूल्य के बजाय भू-राजनीतिक बहस का उपकरण बन जाते हैं। यदि विश्व समुदाय वास्तव में मानवता की रक्षा करना चाहता है तो उसे हर देश के लिए समान मानदंड अपनाने होंगे। इन परिस्थितियों में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दुनिया फिर से उस दौर की ओर बढ़ रही है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नियम बन जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह केवल छोटे देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए गंभीर खतरा होगा।

यदि विश्व समुदाय मिलकर युद्ध के स्थान पर संवाद और सहयोग को अपनाए तो न केवल वैश्विक स्थिरता कायम होगी बल्कि मानवता विकास और समृद्धि के नए मानक भी स्थापित कर सकेगी। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही भविष्य की सबसे बड़ी आशा भी। आज जब विश्व युद्ध, हिंसा और शक्ति-प्रतिस्पर्धा के तनाव से जूझ रहा है, तब दुनिया की निगाहें स्वाभाविक रूप से भारत की ओर उठती हैं। भारत वह धरती है जहाँ शांति, सह-अस्तित्व और अहिंसा केवल राजनीतिक नीतियाँ नहीं बल्कि जीवन-दर्शन के रूप में विकसित हुए हैं।

भारत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने संप्रभुता, गैर-हस्तक्षेप और बहुपक्षीय सहयोग की नीति का समर्थन किया है। भारत का यह विश्वास रहा है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। यही कारण है कि भारत ने हमेशा शांति, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। आज जब विश्व व्यवस्था डगमगा रही है, तब भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत न केवल एक उभरती आर्थिक शक्ति है बल्कि एक ऐसी सभ्यता का प्रतिनिधि भी है जिसने सदियों से अहिंसा, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों को महत्व दिया है। महात्मा गांधी की अहिंसा की परंपरा और भारत की आध्यात्मिक विरासत आज भी विश्व को दिशा दे सकती है।

यदि विश्व समुदाय मिलकर युद्ध के स्थान पर संवाद और सहयोग को अपनाए तो न केवल वैश्विक स्थिरता कायम होगी बल्कि मानवता विकास और समृद्धि के नए मानक भी स्थापित कर सकेगी। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही भविष्य की सबसे बड़ी आशा भी। आज जब विश्व युद्ध, हिंसा और शक्ति-प्रतिस्पर्धा के तनाव से जूझ रहा है, तब दुनिया की निगाहें स्वाभाविक रूप से भारत की ओर उठती हैं। भारत वह धरती है जहाँ शांति, सह-अस्तित्व और अहिंसा केवल राजनीतिक नीतियाँ नहीं बल्कि जीवन-दर्शन के रूप में विकसित हुए हैं। इसी भूमि से वसुधैव कुटुम्बकम का वह महान मंत्र निकला जिसने संपूर्ण मानवता को एक परिवार के रूप में देखने की दृष्टि दी। महात्मा गांधी ने इसी भारतीय परंपरा को आधुनिक युग में अहिंसा की शक्तिशाली राजनीतिक और नैतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया और दुनिया को बताया कि संघर्षों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि सत्य, करुणा और संवाद से संभव है। भारत की आध्यात्मिक विरासत-जिसमें महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों की शिक्षाएँ समाहित हैं, मानवता को यह संदेश देती है कि शांति ही स्थायी विकास और वैश्विक संतुलन का आधार है। आज की अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में भारत की यही अहिंसात्मक दृष्टि, उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सर्वहित की भावना विश्व को एक नई दिशा दे सकती है तथा मानवता को संघर्ष की अंधी दौड़ से निकालकर सहयोग, सद्भाव और स्थायी शांति के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है।

नजरिया

आज जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं भी धूम्रपान से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खतरों के बारे में जागरूक करें। आखिरकार, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ व्यक्तियों से ही होती है। यदि हम तंबाकू से दूरी बनाकर जीवन को अपनाएं तो न केवल अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकते हैं।

धूम्रपान-मुक्त पीढ़ी ही है स्वस्थ भविष्य की बुनियाद

योगेश कुमार गोयल
मोबाइल : 9416740584

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है लेकिन दुर्भाग्य से धूम्रपान और तंबाकू की लत इस अमूल्य धन को तेजी से नष्ट कर रही है। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को 'नो स्मोकिंग डे' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान की आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करना और समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष यह दिवस 11 मार्च को मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा अवसर है, जब लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं और धूम्रपान मुक्त जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हर वर्ष इस दिन एक विशेष थीम के साथ लोगों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। इस वर्ष का संदेश है धूम्रपान से मुक्त जीवन की शुरुआत एक धूम्रपान-मुक्त दिन से होती है।' इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन भी धूम्रपान से दूरी बना ले तो वह आगे चलकर इसे पूरी तरह छोड़ने की दिशा में पहला कदम उठा सकता है।

तंबाकू और निकोटीन की लत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के कारण हर वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से करीब 70 लाख लोग सीधे धूम्रपान करने वाले होते हैं जबकि लगभग 12 लाख लोग ऐसे होते है, जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते लेकिन दूसरों के धुएं के संपर्क में आने के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। यह स्थिति बताती है कि धूम्रपान केवल करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि दुनिया के कई देशों में धूम्रपान करने वालों की संख्या में कमी आई है लेकिन इसके बावजूद चिंता का विषय यह है कि युवाओं और किशोरों में तंबाकू के उपयोग की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 3.7 करोड़ बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ई-सिगरेट और अन्य नए निकोटीन उत्पादों ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इन उत्पादों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन प्रतिबंधों के बावजूद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से युवाओं को लक्ष्य बनाकर प्रचार किया जाता है। इस कारण किशोरों में तंबाकू की लत तेजी से फैल रही है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है।

तंबाकू के दुष्प्रभाव केवल कैंसर तक सीमित नहीं हैं। यह शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है और दुनिया में होने वाली फेफड़ों के कैंसर से लगभग 85 प्रतिशत मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं। इसके अलावा तंबाकू हृदय रोग, स्ट्रोक, दमा, ब्रोंकाइटिस और कई अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करने से मुंह, गले, पेट, लीवर और आंतों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।

तंबाकू की समस्या भारत में भी काफी गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 25 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें अधिकांश पुरुष हैं लेकिन महिलाओं में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में तंबाकू सेवन के कई रूप प्रचलित हैं, जैसे खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और सुपारी के साथ तंबाकू का सेवन। इन उत्पादों की आसान उपलब्धता और कम कीमत के कारण लोग जल्दी इसकी लत के शिकार हो जाते हैं।

धूम्रपान केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देता है। तंबाकू की लत व्यक्ति को धीरे-धीरे निर्भर बना देती है। कई युवाओं में यह लत अवसाद, चिंता और आत्मविश्वास की कमी जैसी मानसिक समस्याओं को भी जन्म देती है। जब किशोरावस्था में यह आदत लग जाती है तो उसे छोड़ना बेहद कठिन हो जाता है और इसका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। धूम्रपान के खतरों को देखते हुए समाज में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। सरकारों ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई कानून बनाए हैं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है और तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी संदेश भी अनिवार्य किए हैं। इसके बावजूद केवल कानून से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत संकल्प दोनों जरूरी हैं। पत्रकारिता के अपने लंबे अनुभव के दौरान मैंने नशे के दुष्प्रभावों पर व्यापक अध्ययन किया है। वर्ष 1993 में मेरी पुस्तक मौत को खुला निमंत्रण' प्रकाशित हुई थी, जिसमें तंबाकू और अन्य नशों से होने वाले भयानक परिणामों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। उस समय भी यह चेतावनी दी गई थी कि यदि समाज ने समय रहते नशे के खिलाफ जागरूकता नहीं बढ़ाई तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। आज तीन दशक बाद भी यह चिंता उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है।

बहरहाल, नो स्मोकिंग डे हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पल अमूल्य है और इसे किसी भी तरह की लत के कारण बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। धूम्रपान छोड़ना कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले और परिवार तथा समाज का सहयोग मिले तो वह आसानी से इस लत से मुक्त हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं भी धूम्रपान से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खतरों के बारे में जागरूक करें। आखिरकार, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ व्यक्तियों से ही होती है। यदि हम तंबाकू से दूरी बनाकर जीवन को अपनाएं तो न केवल अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस नो स्मोकिंग डे पर संकल्प लें कि तंबाकू का साथ छोड़कर हर सांस को कीमती बनाएंगे और जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ईरानी स्कूल पर हमले में अमेरिकी मिसाइल के कथित इस्तेमाल का नया वीडियो आया सामने

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यरुशलम/एपी। एक नए वीडियो फुटेज से यह आशंका मजबूत हुई है कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में एक परिसर पर अपनी टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया था। यह परिसर उस स्कूल के पास स्थित है, जहां पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की शुरुआत में हुए विस्फोट में 165 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

जांचकर्ताओं का कहना है कि 28 फरवरी को हुआ यह हमला ईरान के मिनाब शहर में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के एक ठिकाने के पास स्थित स्कूल के निकट हुआ था। यह क्षेत्र होरमोजगन प्रांत में आता है।

इस हमले का एक नया वीडियो सामने आया है जिसकी जांच 'बेलिंगकैट' नामक जांच समूह ने की। इस वीडियो में एक मिसाइल को इमारत से टकराते और आसमान में काला धुआं उठते हुए देखा गया है।

समाचार एजेंसी 'एसोसिएटेड प्रेस' ने इस वीडियो की भौगोलिक स्थिति की जांच में पाया कि इसे स्कूल के पास के ही इलाके से रिकॉर्ड किया गया था, जहां पहले से ही धुआं उठ रहा था।

बेलिंगकैट समूह के शोधकर्ता ट्रेवर बॉल ने हमले में इस्तेमाल हथियार की पहचान टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के रूप में की है,जो केवल अमेरिका के ही पास मौजूद है। 'यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड' ने इस युद्ध में टॉमहॉक मिसाइलों के इस्तेमाल की पुष्टि की है और 28 फरवरी को यूएसएस स्प्रुएन्स द्वारा मिसाइल दागे जाने की तस्वीर भी जारी की थी। यह जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत समूह का हिस्सा है, जो हमले के इलाके की मारक दूरी में था।

बेलिंगकैट ने कहा कि यह फुटेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन करता हुआ लग रहा है, जिसमें उन्होंने घातक विस्फोट के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था।

ट्रंप ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईरान के पास भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल हो सकती है। यह मिसाइल अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियोन बनाती है और जापान व ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों को बेची जाती है। ईरान के पास इसके होने का कोई प्रमाण नहीं है।

ट्रंप ने कहा, यह मिसाइल कई देशों को बेची जाती है और इस्तेमाल की जाती है। ईरान के पास भी कुछ टॉमहॉक हो सकते हैं। इस बीच, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका इस घटना की जांच कर रहा है।

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी घटना में अमेरिकी सेना की संभावित भूमिका सामने आती है तो उसकी समीक्षा शुरू की जाती है। इसी के तहत इस हमले का भी आकलन किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल की लोकेशन भी इस आशंका को बल देती है, क्योंकि वह रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने और नौसैनिक इकाई की बैरक के पास स्थित है। अमेरिका पहले ही इस प्रांत में नौसैनिक लक्ष्यों पर हमले की बात स्वीकार कर चुका है।

श्रीलंका ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आठ प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की

कोलंबो/भाषा। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में आई तेजी के बीच श्रीलंका ने सोमवार आधी रात से खुदरा ईंधन कीमतों में आठ प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पेट्रोल एवं डीजल की खुदरा कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय की गई है जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें चार साल में पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं।

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) ने कहा कि संशोधित दरों के तहत व्यापक रूप से उपयोग होने वाले पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 22 श्रीलंकाई रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने कहा कि यह कदम ईंधन की जमाखोरी और घबराहट में की जा रही खरीद को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सीपीसी के एक अधिकारी ने कहा, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति की खबर आने के बाद से ईंधन की खपत में भारी वृद्धि देखी गई है।

सहायता

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को 'ओरुनोडोई' योजना के तहत वित्तीय सहायता हस्तांतरित की। इस योजना के माध्यम से राज्य के महिला-प्रधान परिवारों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी गई है।

चीन का निर्यात जनवरी-फरवरी में 22 प्रतिशत बढ़ा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हांगकांग/एपी। अमेरिका के साथ व्यापार में कमी आने के बावजूद चीन का निर्यात वर्ष 2026 के पहले दो महीनों में सालाना आधार पर लगभग 22 प्रतिशत बढ़ गया।

चीन के सीमा शुल्क प्रशासन की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-फरवरी 2026 की अवधि में चीन का आयात लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दिसंबर में यह वृद्धि 5.7 प्रतिशत थी। अमेरिका से चीन के आयात में सालाना आधार पर लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि इस अवधि में निर्यात में 22 प्रतिशत की वृद्धि अर्थशास्त्रियों के अनुमान से अधिक रही। यह दिसंबर में दर्ज 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी ज्यादा है।

अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन का निर्यात बढ़ना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। वर्ष 2025 में चीन का निर्यात 5.5 प्रतिशत बढ़ा और उसका व्यापार अधिशेष बढ़कर लगभग 1.2 लाख करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

हालांकि पिछले दो महीनों में चीन से अमेरिका को होने वाले निर्यात में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन इस दौरान यूरोप एवं लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है।

जनवरी-फरवरी अवधि में चीन का वैश्विक व्यापार अधिशेष 213.6 अरब डॉलर रहा। चीन आम तौर पर इन दो महीनों के व्यापार आंकड़े एक साथ जारी करता है ताकि चंद्र नववर्ष अवकाश के कारण होने वाले मौसमी प्रभाव को कम किया जा सके। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पिछले कुछ वर्षों से संपत्ति क्षेत्र में मंदी के कारण दबाव में है। यही कारण है कि चीन ने वर्ष 2026 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 4.5 से 5.0 प्रतिशत तय किया है जो 1991 के बाद सबसे कम है।

जामनगर रिफाइनरी में एलपीजी का उत्पादन अधिकतम किया जाएगा : रिलायंस

नयी दिल्ली/भाषा

उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को कहा कि उसका विशाल जामनगर तेल रिफाइनरी परिसर रसोई गैस एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करेगा, जबकि बंगाल की खाड़ी के केजी-डी6 क्षेत्र से गैस को प्राथमिक क्षेत्र को उपलब्ध कराने के लिए मोड़ा जाएगा, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशिया में युद्ध से होने वाले व्यवधानों से उबरने में मदद मिल सके। कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब सरकार ने औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को घरेलू उपभोक्ताओं की ओर मोड़ दिया है, ताकि आम आदमी को पश्चिम एशिया में युद्ध के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।

उपलब्धि

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित 'उल्लास: नव-साक्षरों का अलंकरण समारोह' में नए साक्षरों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 99.93 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर ली है।

मिडलाइफ कोई संकट नहीं बल्कि महिला की असली ताकत का उदय है : लिसा रे

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म 'कसूर' से भारतीय सिनेमा में लोकप्रियता हासिल करने वाली कनाडाई-भारतीय अभिनेत्री लिसा रे अब भले ही स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वे सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर बात करती रहती हैं। लिसा रे ने मंगलवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने विचार व्यक्त किए। इस पोस्ट में उन्होंने मिडलाइफ के बारे में अपने भाव व्यक्त किए। अभिनेत्री ने लिखा, जब शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, तो कई बदलाव आते हैं। लोग अब दूसरों को खुश करने की पुरानी आदत छोड़ देते हैं। खुद पर शक करना कम हो जाता है और मन की शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है। वहीं, अपनी बनाई गई सीमाएं और नियम मजबूत होने लगते हैं।

लिसा ने लिखा, मिडलाइफ वह दौर है जब हार्मोन के बदलाव के साथ-साथ जिंदगी की बेकार चीजें भी दूर हो जाती हैं। अब कम माफी मांगते हैं, कम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। अपनी कीमत खुद समझ आती है। जरूरत पड़ने पर साफ 'ना' कहना आसान हो जाता है और जीवन ज्यादा सुकून से जीने लगता है।

अपनी बात को खत्म करते हुए अभिनेत्री ने लिखा कि मिडलाइफ कोई संकट या क्राइसिस नहीं है बल्कि यह वह खास समय है जब महिला अपनी असली ताकत के साथ जीना शुरू करती है। यह जीवन की कहानी का दूसरा हिस्सा होता है, जो आखिरकार पूरी तरह उसका अपना होता है। सच तो यह है कि महिलाओं की जिंदगी का यह सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दौर होता है। लिसा रे 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने साल 1994 में फिल्म 'हंसते खेलते' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन असल पहचान उन्हें फिल्म कसूर से मिली थी। इसके बाद वे 'वाटर' और 'आई कांट थिंक स्ट्रेट' जैसी फिल्मों में नजर आई थीं। हालांकि, करियर के पीक पर ही उन्हें कैंसर हो गया था और उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। हालांकि अब वह ठीक हैं और उन्होंने कैंसर से जंग जीत ली है।

आपत्तिजनक पोस्ट मामले में भोजपुरी एक्ट्रेस को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को दी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली/एजेन्सी

सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत दे दी है है, हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। इस पोस्ट को लेकर लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के पहले दिए गए निर्देश के अनुसार नेहा सिंह राठौर जांच अधिकारियों के सामने पेश हो चुकी हैं और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है।

इसी आधार पर अदालत ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें आगे भी जांच में पूरा सहयोग करना होगा। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी।

उस समय अदालत ने निर्देश दिया था कि नेहा सिंह राठौर को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पहली बार 9 जनवरी को उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। दरअसल यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है।

आरोप है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ऐसे बयान लिखे थे, जिन्हें आपत्तिजनक और भड़काऊ माना गया। इसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी पोस्ट से दो समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है और इससे सामाजिक माहौल खराब हो सकता है।

एफआईआर में यह भी कहा गया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। इस संवेदनशील घटना के बाद राठौर की ओर से किए गए कथित पोस्ट को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इस तरह के बयान देश की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने मंगलवार को मुंबई में अपने पति जैकी भगनानी के साथ फोटोग्राफरों के लिए पोज दिए।

टीवी के बाद अब ओटीटी पर जादू बिखेरेंगी रूप दुर्गापाल

मुंबई/एजेन्सी

'स्वरागिनी,' 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी,' और 'बालवीर' जैसे कई धारावाहिकों में काम कर घर-घर में अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री रूप दुर्गापाल अब ओटीटी डेब्यू करने जा रही हैं। दरअसल, अभिनेत्री जल्द ही आगामी वेब सीरीज 'संकल्प' में नजर आएंगी। इस सीरीज में वे अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब की पत्नी माधुरी के किरदार में हैं। रूप ने अपने को-स्टार जीशान के अभिनय की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जीशान बहुत ही शानदार अभिनेता है। एनएसडी से पढ़ाई करने और फिल्मों-वेब सीरीज में इतना अनुभव होने के कारण उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके सीन्स को देखने का नजरिया, भाषा पर अच्छी पकड़ और एनर्जी ने मेरे साथ के सीन को बेहतर बनाया। मैं हर दिन सेट पर उनके आने का इंतजार करती थी। अभिनेत्री ने आगे सीरीज की पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने बताया कि शानदार कलाकारों के साथ काम करना ही उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उत्साहित कर रहा था। अभिनेत्री ने कहा, जब सबके पास अच्छा काम होता है, तो सेट पर और बाहर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाना पाटेकर सर और प्रकाश सर के साथ काम करना एक्टिंग, फिल्म बनाने और जिंदगी के कई पहलुओं को समझने जैसा था। मेघना मलिक से भी बहुत कुछ सीखा। हम लंच और डिनर के दौरान भी खूब बातें करते थे। वे न सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं।

उन्होंने आगे बताया कि सीरीज के लिए उन्हें ऑफर कैसे मिला था। उन्होंने बताया, साल 2019 तक मैंने टेलीविजन से आगे जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन कोविड के दौरान सब कुछ बदल गया। लोगों को जाते देखकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तब मैंने फैसला लिया कि अब उन चीजों को आजमाना है जिनसे पहले डर लगता था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली अभिनेत्री रूप ने सिल्वर स्क्रीन पर परफॉर्म करने के अलावा, थिएटर में भी काम किया, जो उनके लिए नया था। उन्होंने थिएटर को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया, बिना कट, रीटेक के, महीनों रिहर्सल करके स्टेज पर परफॉर्म करना काफी अजीब था, लेकिन जिंदगी की अनिश्चितता ने मुझे हिम्मत दी। स्टेज पर खड़े होकर बिना किसी डर के परफॉर्म करना शानदार अनुभव था। इसी हिम्मत ने मुझे टीवी से आगे बढ़कर वेब सीरीज में आने की ताकत दी। अभिनेत्री का मानना है कि हर किसी का सफर अलग होता है और सब कुछ अपने सही समय पर ही होता है। उन्होंने कहा, शायद मेरा सफर ऐसा ही होना था। सालों की संख्या मायने नहीं रखती। मैं बहुत खुश हूं कि यह सब अपने आप हुआ। सीरीज का निर्देशन प्रकाश झा ने किया है। रूप ने निर्देशक की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रकाश सर के साथ काम करना किसी बड़े संस्थान में पढ़ाई करने जैसा था। साथ ही काम में मजा भी आता था और यादगार पल भी बनते थे।

इंदौर के संगीत घराने से ताल्लुक रखने वाले शाहबाज ने चुनी अभिनय की राह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर। कहते हैं कि भाग्य कहां ले जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे स्टार्स आए, जो किसी दूसरे प्रोफेशनल से ताल्लुक रखते थे। ऐसे ही सिनेमा और टीवी पर चमकने वाले अभिनेता शाहबाज खान को भी नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है लेकिन भाग्य और मेहनत के भरोसे उन्होंने फैंस के दिलों पर राज किया और आज भी टीवी पर अपने निगेटिव किरदारों से राज कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनेता के पिता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को नया रूप दिया था। 10 मार्च को इंदौर में जन्मे शाहबाज शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक उस्ताद अमीर खान थे, जिन्होंने आज गावत मन मोरा झूम के, जिन के मन में राम बिराजे और बैरागी रूप धरे जैसे गाने गाए थे। उनके दादा शामीर खान भी सारंगी वादक थे। इतने बड़े घराने से आने के बावजूद भी अभिनेता को संगीत से दूर रखा गया क्योंकि उनकी मां ही नहीं चाहती थी कि वो गायक बनें। दरअसल, अभिनेता की मां नहीं चाहती थी कि भरी महफिल में कोई यह कहे कि उस्ताद अमीर खान का बेटा कैसा गाता है। जब शाहबाज छोटे थे, तभी उनके पिता

का निधन हो गया और उस वक्त उन्हें संगीत की तालीम देने वाला कोई नहीं था। अगर वे किसी और घराने में संगीत सीखने जाते तो कई तरह की बातें होतीं। अभिनेता ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि मां ने कहा था कि भले ही रिक्शा चला ले लेकिन संगीत नहीं सीखना है।

अभिनेता की शुरुआती पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अकेले खुद को संभालना सीखा। वह छोटी उम्र में ही समझदार बन चुके थे लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भाग्य उन्हें सिनेमा की तरफ लेकर जाने वाला है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें नहीं पता था कि करना क्या है लेकिन एक दोस्त के बुलाने पर मुंबई चले गए,जहां उन्होंने कई महीनों तक थिएटर सीखा और उनकी किस्मत तब चमकी, जब उन्हें टीवी सीरीज 'टीपू सुल्तान' में हैदर अली का रोल मिला। पहले टीवी सीरीज कुछ ही एपिसोड में खत्म होने वाली थी लेकिन अभिनेता की किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने 58 एपिसोड तक काम किया। टीपू सुल्तान शाहबाज़ को पहचान दिलाने के लिए काफी था। उन्हें उर्दू की बेहतर समझ के चलते सीरियल ऑफर हुआ, जिसके बाद वो 'चंद्रकांता', 'बेताल पचीसी' और 'द ग्रेट मराठा' जैसे सीरियल में दमदार रोल में दिखे। सीरियल में पहचान बनाने के बाद उन्होंने फिल्मों का रूख किया। शुरुआत भले ही फिल्म 'नाचनेवाले गानेवाले' से हुई, लेकिन बाद में कैसे-कैसे रिश्ते, धरतीपुत्र, जिद्दी, युग और मेजर साब जैसी फिल्मों में सिनेमा के खरतनाक विलेन बनकर उभरे। आज भी अभिनेता टीवी और ओटीटी की दुनिया पर राज कर रहे हैं।

RNI No. : TNHIN/2013/52520 Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016 posted at Patrika Channel, Egmore RMS, Chennai-8

श्री आदिनाथ भगवान के जन्म-दीक्षा कल्याणक एवं

श्री आदिनाथ जैन मंडल के 48वें वार्षिकोत्सव पर आदिनाथ जैन ट्रस्ट, चूलै, चेन्नई

को एक और महत्वपूर्ण सेवा अवसर प्राप्त होने जा रहा हैं ।

हमारे ट्रस्ट की सेवा गतिविधियों तथा पूर्व में तमिलनाडु सरकार द्वारा समर्पित कोलत्तूर हॉस्पिटल के सफल संचालन से अति प्रभावित होकर अब

नूतन नवनिर्मित मानव सेवा केन्द्र, अन्ना पिल्लै स्ट्रीट, साहुकारपेट

स्थित बहु मंजिला हॉस्पिटल सह सेवा केन्द्र हमारे ट्रस्ट को सहर्ष समर्पित किया जायेगा ।

ADINATH® JAIN TRUST (Since 1979) Choolai, Chennai

CMDA एवं **GCC** द्वारा **जीर्णोद्धारित मानव सेवा केन्द्र का निर्माण** तमिलनाडु सरकार के Hon. Chief Minister **MK STALINJI** एवं थिरु **शेखर बाबु** के अथक प्रयासों से किया गया है ।

इस केन्द्र में जरुरतमंद लोगों के लिए आर्टिफिसीयल एवं **मोड्यूलर लिम्ब, फिजीयोथेरिपी, रिहैबिलिटेशन सेंटर आदि निःशुल्क सेवाएँ दी जायेगी ।**

इस अवसर पर तमिलनाडु सरकार की विश्वस्तता हेतु अंतःकरण से धन्यवाद सह आभार ज्ञापित करता हैं ।

सभी बंधुगण मंगलकामना प्रेषित करने हेतु सादर आमंत्रित हैं ।

उद्घाटन कर्ता : Hon. Chief Minister **MK STALINJI**

दि. **11.3.2026,** बुधवार, प्रातः **11.00** बजे

मानव सेवा केन्द्र, अन्नापिलाई स्ट्रीट, साहुकारपेट, चेन्नई

|| ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रमुख सेवाएँ ||

जैनोलॉजी, जैन विद्या, तत्त्वज्ञान, कर्मग्रंथ कोर्स, वैयावच्च, स्वाध्याय, आयंबिल खाता, सामुहिक वर्षीतप, कृत्रिम पैर, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड, टेलरिंग, फिजीयोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, न्यूरो, त्वचा, दंत, नेत्र चिकित्सा, जनरल क्लिनिक आदि साथ ही ब्याज मुक्त साधर्मिक लोन, व्यापार विकास योजनाएँ, मेडिकल डिस्काउंट कार्ड, संगीत-शिक्षा तथा विभिन्न शिक्षा-प्रशिक्षण शिबिर भी संचालित किए जाते हैं ।

पालिताणा में सर्व समुदाय के साधु-साध्वी भगवंत के लिए उपाश्रय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ग्रंथालय, भोजनशाला, डोरमेटरी एवं बहुउद्धेशिय सभा गृह प्रारंभ हो चुका है ।

अशोक वैद अध्यक्ष 98402 54400 **डॉ. मोहन जैन** सचिव 72009 25499

NAVKAR 9840098686

Best Wishes From :

KRISHII FIBER
INTERNET | IPTV | OTT | VOICE | DTH

स्व. श्री अशोकचंदजी - शांतिबाई खिंवसरा
महावीरचंद, दीपक - दिपीका,
क्रिशी, पारुशी खिंवसरा, ताम्बरम्-सेल्यूर

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.